

मुकदमों का विवरण

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई

वी.

मैसर्स गणपति ने अपने मालिक श्री यशपाल शर्मा और ए. एन. आर. के माध्यम से ओवरसीज किया।

(सिविल अपील सं. 2009 की 4735-4736) अक्टूबर 06, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या न्यायाधिकरण को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि आयातित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नोटिस-प्रत्यर्थियों पर लगाए गए दंड को कायम नहीं रखा जा सका और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अलग कर दिया गया।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-14-सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 -आर. 4, 8, 5, 6 और 7-आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य-उत्तरदाताओं द्वारा मूल्य के कम चालान और इस तरह सीमा शुल्क की चोरी के आरोपों का निर्धारण-हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं के पहले सेट में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर कार्यवाही की शुरुआत-निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित मूल्य और आयात चालान के अनुसार माल की कीमत में विसंगतियां देखी गईं-निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट को दाखिल करना, हालांकि प्रारंभिक चरण में मूल्य की गलत घोषणा के लिए जुर्माना लगाया गया था, जो विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था-आयात चालान के अनुसार घोषित मूल्य को अस्वीकार करने के बाद विभाग 8 आरआर से गुजरने के बजाय तुरंत 5, 6 और 7 क्रमिक रूप से-शुद्धता

आयोजित किया गया: यदि आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य आरआर के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाएगा। 5 8 तक-जहां आयातित वस्तुओं का मूल्य आर. आर. 5 से 7 ए के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां मूल्य का निर्धारण आर. में दिए गए उचित साधनों का उपयोग करके किया जाएगा। 8-अवशिष्ट विधि-इसके अलावा, लेनदेन मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है यदि चालान मूल्य सही नहीं पाया जाता है

लेकिन यह साबित करना विभाग का काम है कि चालान मूल्य गलत है-तथ्यों पर, विभाग के साथ-साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दोनों को माल के आयात चालान मूल्य को सही नहीं बताते हुए अस्वीकार करने और सीधे आर का आह्वान करके मूल्य बढ़ाने के लिए उचित नहीं ठहराया गया था।⁸ जब उनके सामने ऐसा करने के लिए कोई सबूत नहीं था-इस प्रकार, न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने में न्यायसंगत ठहराया गया था-न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए विवादित फैसले में कोई त्रुटि या असंवेदनशीलता नहीं थी।[पैरा 34.1,37,40.2,41,42]

सीमा शुल्क अधिनियम, **1962**-विदेश से आयातित माल की कीमत को कम करने और इस तरह से नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा सीमा शुल्क से बचने का आरोप लगाने वाली कार्यवाही की शुरुआत-सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं के पहले सेट की अप्रमाणित फोटोकॉपी पर निर्भरता जो निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित कीमत और आयात चालान के अनुसार माल की कीमत में बड़ी विसंगति दर्शाती है-न्यायसंगत कथन -

आयोजित किया गया:विभाग और इससे पहले राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जिन निर्यात घोषणाओं पर भरोसा किया गया था, वे अप्रमाणित फोटोकॉपी थीं-चूंकि उन दस्तावेजों का उपयोग नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ सबूत के एक टुकड़े के रूप में किया गया था, इसलिए यह आवश्यक था कि उन दस्तावेजों को साबित किया गया हो-जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनकी अप्रमाणित फोटोकॉपी का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा-इन दस्तावेजों के बहुत से आधार को बाद में हटा दिया गया था जब विदेशी आपूर्तिकर्ता ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के सामने निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट का नेतृत्व किया था, जिसमें आयात चालान में घोषित माल की कीमत के बराबर कम कीमत दिखाई गई थी-विदेशी आपूर्तिकर्ता ने प्रारंभिक चरण में कीमत की गलत घोषणा के लिए जुर्माना अदा किया था-इसमें कोई औचित्य नहीं हो सकता है। [पैरा 16,17]

सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** -धारा **108**-साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति-दर्ज किए गए बयान के साक्ष्य में स्वीकार्यता।**108**:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आयोजित किया गया:सीमा शुल्क अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं है, और वह व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है और जो यू/एस के तहत बयान देता है।**108** अभियुक्त नहीं है-हालाँकि, एक व्यक्ति यू/एस द्वारा दिया गया बयान।**108** संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष साक्ष्य स्वीकार्य है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है-वस्तु अंतर्निहित एस।**108** सीमा शुल्क उल्लंघन की घटना के संबंध में जिस व्यक्ति से सच्चाई का पता लगाया जा रहा है, इस प्रकार सीमा शुल्क अधिकारी को इस प्रकार दर्ज किए गए बयान की सच्चाई सुनिश्चित करनी चाहिए-यदि दर्ज किया गया बयान सही नहीं है, तो इस तरह के बयान को दर्ज करने की बहुत

उपयोगिता समाप्त हो जाएगी-यह स्वयंसिद्ध है कि जब कोई बयान साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में स्वीकार्य है, तो उसे न्यूनतम न्यायिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए-बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ दबाव या जबरदस्ती के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग नहीं किया जा सकता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को उसी को लागू करना है-तथ्यों पर, आपूर्तिकर्ता के निदेशक और आयातक के मालिक का बयान, यू/एस दर्ज किया गया है।¹⁰⁸ जिसमें दोनों को मूल्यांकन के तहत स्वीकार किया गया-न्यायाधिकरण ने बयान को वापस लेने के तथ्य को नोट किया और इस प्रकार, इस तरह के बयान को विश्वसनीयता देने से इनकार कर दिया-न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण न्यायसंगत है।[पैरा 18,20,28]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम दक्षिण भारत टेलीविजन (पी)

लिमिटेड (2007) 6 एससीसी 373:[2007] 8 एस. सी. आर. 95; रवीन्द्र चंद्र पॉल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, (2007) 3 एस. सी. सी. 93:[2007] 3 एस. सी. आर. 319-पर निर्भर।

सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ, 1997 (89) ई. एल. टी.-646; के. आई.

पावन्नी बनाम सहायक कलेक्टर (1997) 3 एस. सी. सी. 721:[1997] 1 एससीआर 797;

पंजाब राज्य बनाम बरकत राम [1962] 3 एस. सी. आर. 338; रमेश चंद्र मेहता

बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 940:[1969] एस. सी. आर. 461; कलेक्टर

सीमा शुल्क विभाग, मद्रास बनाम डी. भूरमल (1974) 2 एस. सी. सी. 544:[1974] 3 एस. सी. आर. 833; नरेश जे. सुखवानी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 522:[1995] 4 पूरक।एससीआर 778; के. आई. पावन्नी बनाम सहायक कलेक्टर (1997) 3 एस. सी. सी. 721:[1997] 1 एस. सी. आर. 797; भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 254:[2008] 14 एससीआर 179; आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाम आयुक्त

सीमा शुल्क (2001) 1 एस. सी. सी. 315:[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 597-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 4735-4736।

2002 के अपील No.C/1347 और 1374 में मुंबई में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 27.06.2008 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

बीर सिंह, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, रुपेश कुमार, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, अनिरुद्ध शर्मा द्वितीय, ईशान शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री नेहा चौधरी, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, सुश्री फाल्गुनी गुप्ता, सुश्री उमंग मोटियानी, एम. पी. देवनाथ, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

उज्जल भुवन, जे।

1. चूंकि दोनों अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 27.06.2008 के अंतिम आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें पक्ष भी समान होते हैं, इसलिए दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई ने 2002 की अपील संख्या सी/1347 और 1374 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई की पश्चिम क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित सामान्य निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक आई. डी. 1 के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130-ई के तहत अपील की है।

3. दोनों अपीलों में जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या सी. ई. एस. टी. ए. टी. को आयातित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और सीमा शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन-1) द्वारा लगाए गए दंड को उचित ठहराते हुए न्यायसंगत ठहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उत्तरदाताओं पर मुंबई को कायम नहीं रखा जा सका और इसके परिणामस्वरूप इसे अलग रखा जा सका?

4. तथ्यों का एक संक्षिप्त पाठ क्रम में होगा।

4.1. अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा उत्तरदाताओं को दिनांकित 17.12.1999 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय को गुप्त सूचना मिली थी कि मैसर्स गणपति ओवरसीज ने चालान की कीमतों से काफी कम कीमत पर हांगकांग से ट्यूनर का आयात किया था, जिससे भारी सीमा शुल्क से बचा जा सकता था। जानकारी से पता चला कि एफ. आई. आर. एम. मैसर्स गणपति ओवरसीज का स्वामित्व श्री यशपाल शर्मा के पास था; हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता मैसर्स एरिस एंटरप्राइजेज का स्वामित्व उनके रिश्तेदार श्री सुरेश चंद्र शर्मा के पास था; आयातित वस्तुओं को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, मुंबई से मंजूरी दी गई थी और मैसर्स नेशनल शिपिंग एजेंसी, मुंबई ने सीमा शुल्क हाउस एजेंट के रूप में काम किया था।

4.2. ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, राजस्व खुफिया निदेशालय ने जांच की जिससे यह पता चला कि मैसर्स गणपति ओवरसीज ने 1997-98 और 1998-99 वर्षों के दौरान बीस खेपों का आयात किया था। यह पाया गया कि मैसर्स गणपति ओवरसीज ने मुख्य रूप से मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज, हांगकांग से ट्यूनर का आयात किया था और ट्यूनर के साथ आरा फाई एल्टर की लगभग तीन-चार खेपों का भी आयात किया था। राजस्व खुफिया निदेशालय ने हांगकांग में भारत के वाणिज्य दूतावास से जानकारी प्राप्त की कि मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज, हांगकांग श्री सुरेश चंद्र शर्मा से संबंधित है जो अपनी पत्नी श्रीमती कुसुम शर्मा के साथ निदेशक थे। जब श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने मार्च, 1999 में भारत की यात्रा की थी, तो उनका बयान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 (जिसे इसके बाद 'सीमा शुल्क अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत आईडी1 पर दर्ज किया गया था। श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मैसर्स गणपति ओवरसीज श्री यशपाल शर्मा के थे जो उनके सह-भाई थे। उन्होंने कहा कि मैसर्स गणपति ओवरसीज 1997-98 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात के व्यवसाय में था। उन्होंने हांगकांग से अपने मैसर्स एरीज एंटरप्राइजेज के माध्यम से मैसर्स गणपति ओवरसीज को ट्यूनर और सॉ फाइटर की आपूर्ति की थी।

4.3. श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने स्वीकार किया कि मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज द्वारा चालान में दिखाए गए प्रति पीस ट्यूनर की दर वास्तविक कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करती है। उन्होंने जानबूझकर अपने सह-भाई द्वारा आयातित वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क बचाने के इरादे से कम कीमत का उल्लेख किया था, 177

श्री यशपाल शर्मा। ट्यूनों की वास्तविक कीमत काफी अधिक थी। वास्तविक मूल्य और घोषित मूल्य के बीच के अंतर को भारत में बरकरार रखा गया था जिसे वे श्री यशपाल शर्मा से एकत्र करते थे।

4.4. श्री यशपाल शर्मा को भी तलब किया गया था, जिसके बाद उनका बयान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत 15.03.1999 पर दर्ज किया गया था। सीमा शुल्क से बचने के लिए वास्तविक मूल्य से बहुत कम मूल्य दिखाकर माल के आयात के तथ्य का वर्णन करने के अलावा, उन्होंने कहा कि आयात दस्तावेजों में बताए गए भुगतान की राशि उनके द्वारा श्री सुरेश चंद्र शर्मा को बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजी गई थी, जबकि शेष अलग-अलग राशि श्री सुरेश चंद्र शर्मा को उनकी भारत यात्राओं पर सौंपी जाती थी।

4.5. यह उल्लेख किया गया था कि बिक्री वाउचर के अनुसार आयातित ट्यूनों की कीमत रुपये के दायरे में थी। 40-60 प्रति टुकड़ा लेकिन इन ट्यूनों का वास्तविक बाजार मूल्य रु। 200-325 प्रति टुकड़ा। इस तरह, उत्तरदाताओं ने कुल लगभग बीस से तीस लाख रुपये की सीमा शुल्क की चोरी की थी।

4.6. श्री यशपाल शर्मा को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत 15.03.1999 पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा 30.03.1999 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था, बशर्ते कि दस लाख रुपये की राशि राजस्व खुफिया निदेशालय के कार्यालय में 30.03.1999 पर जमा की जानी चाहिए और चालीस-पाँच दिनों की अवधि के भीतर बीस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की जानी चाहिए। तदनुसार दोनों राशि जमा की गई।

4.7. निर्यात घोषणाओं सहित प्रासंगिक सामग्रियों की जांच से यह पाया गया कि हांगकांग सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष निर्यातक के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं के अनुसार ट्यूनों की कीमत हांगकांग डॉलर प्रति पीस थी जो माल के आयात के समय भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स गणपति ओवरसीज द्वारा चालान में घोषित कीमत की तुलना में बहुत अधिक थी। इस संबंध में, राजस्व खुफिया निदेशालय ने दो चार्ट तैयार किए; चार्ट-I के अनुसार, मेसर्स गणपति ओवरसीज ने 500 करोड़ रुपये की सीमा तक सीमा शुल्क की चोरी की थी। 1,07,41,419.00 उन्नीस खेपों के आयात पर। इसी तरह, राजस्व खुफिया निदेशालय ने चार्ट-II तैयार किया जो ताइवान में बनाए गए 3200 ट्यूनों के आयात से संबंधित था। यह उल्लेख किया गया है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष घोषित माल का मूल्य हांगकांग \$19200 था जबकि हांगकांग सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष निर्यात घोषणा के अनुसार वास्तविक मूल्य

हांगकांग \$211468.07 था। इस प्रकार, राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार, मेसर्स गणपति ओवरसीज ने 500 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की चोरी की थी। 8, 67, 762.00। मेसर्स गणपति ओवरसीज द्वारा आयात दस्तावेजों में दिखाए गए माल की कीमत माल की वास्तविक कीमत से बहुत कम पाई गई, यानी उस कीमत पर जिस पर उन्हें हांगकांग से आपूर्ति की गई थी। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 और सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 (संक्षेप में, इसके बाद 'सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम') के संदर्भ में आयात मूल्यांकन को खारिज कर दिया गया था।

4.8. कारण दर्शाओ नोटिस में प्रस्ताव दिया गया है कि आयातित वस्तुओं का मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 के तहत हांगकांग सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से प्राप्त निर्यात घोषणाओं में दिए गए मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह आरोप लगाते हुए कि उत्तरदाताओं ने सीमा शुल्क से बचने के इरादे से जानबूझकर आयातित वस्तुओं के सही मूल्य की गलत घोषणा की और उसे दबा दिया, राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 (1) के प्रावधान के अनुसार सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान किया। यह उल्लेख किया गया था कि मेसर्स गणपति ओवरसीज रुपये के अलग-अलग सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। चार्ट-I के अनुसार ट्यूनर, आरा फिटर आदि के आयात पर 1,07,41,419.00 और रु। 8, 67, चार्ट-II के अनुसार, कुल राशि रु। 1,16,09,181.00। इसलिए प्रत्यर्थियों से कारण बताने के लिए कहा गया कि उनसे सीमा शुल्क की उपरोक्त राशि की मांग और वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए और यह भी कि आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और 111 (एम) के तहत क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 30 लाख पहले ही जमा किए जा चुके हैं। उत्तरदाताओं से आगे कारण बताने के लिए कहा गया कि उन पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (ए) के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और चोरी किए गए सीमा शुल्क पर ब्याज क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

4.9. नोटिसों को निर्धारित समय के भीतर सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर हवाई अड्डा, मुंबई को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के प्रावधान के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 124 के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

179

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 180

5. मेसर्स गणपति ओवरसीज ने अपने वकील के माध्यम से 20.05.2000 पर उपरोक्त कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब दिया। सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए, यह उल्लेख किया गया कि सीमा शुल्क आयुक्त ने अपने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से मेसर्स गणपति ओवरसीज के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि बचाव की तैयारी करते समय उन दस्तावेजों

की प्रासंगिकता हो सकती है और उन दस्तावेजों की अनुपस्थिति उचित बचाव करने में नोटिसों को बाधित करेगी। इस तरह के दस्तावेजों के लिए अनुरोध को दोहराते हुए, नोटिसों ने एक अंतरिम जवाब प्रस्तुत किया।

5.1. यह उल्लेख किया गया था कि श्री यशपाल शर्मा सूचना प्राप्तकर्ता एफ. आई. आर. एम. के मालिक थे जो 1997-98 और 1998-99 वर्षों के दौरान ट्यूनर आदि के आयात के व्यवसाय में लगे हुए थे। ये आयात मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज, हांगकांग से किए गए थे। मंजूरी के समय, प्रवेश के बिल सीमा शुल्क हाउस एजेंट के माध्यम से भेजे जाते थे और आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क के भुगतान पर सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद मंजूरी दी जाती थी। उन वस्तुओं को बाद में स्थानीय बाजार में बेचा गया। कुल मिलाकर बीस खेपों का आयात किया गया था। इसके बाद नोटिसों में दो प्रकार के ट्यूनों का विवरण दिया गया और प्रस्तुत किया गया, जिन्हें लगभग नौ महीने की अवधि में आयात किया गया था, जिसमें बीस खेपें थीं।

5.2. नोटिसकर्ताओं ने कारणदर्शक नोटिस में लगाए गए आरोपों की ओर इशारा किया कि नोटिसकर्ताओं द्वारा घोषित कीमत सही नहीं थी और कम थी, जैसा कि श्री सुरेश चंद्र शर्मा और श्री यशपाल शर्मा के सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयानों के साथ-साथ हांगकांग सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष मैसर्स एरीज एंटरप्राइजेज के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं द्वारा साबित होता है। यह बताया गया कि श्री सुरेश चंद्र शर्मा और श्री यशपाल शर्मा के दो बयानों को किसी भी परिस्थिति में स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता है। उन अपमानजनक बयानों को जबरदस्ती और दबाव में प्राप्त किया गया था। यह बताया गया कि श्री यशपाल शर्मा के बयान को इस तरह से संरचित किया गया था कि यह पूरी तरह से श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयान से मेल खाता हो। इसके अलावा, श्री यशपाल शर्मा का बयान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष दिए गए उनके अपने बयान के विपरीत था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आयातित वस्तुओं का कोई कम मूल्यांकन या कम चालान नहीं था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि दोनों बयान नहीं थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सभी विश्वसनीय। इसके अलावा, श्री यशपाल शर्मा ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने द्वारा दिए गए बयान को वापस ले लिया था। 3. 3. मैसर्स एरिस एंटरप्राइजेज के नेतृत्व में हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह ज्ञात नहीं था कि ये घोषणाएं भारत के वाणिज्य दूतावास, हांगकांग द्वारा राजस्व खुफिया निदेशालय, नई दिल्ली को कब भेजी गई थीं। विभाग द्वारा जिन प्रतियों पर भरोसा किया गया था वे अप्रमाणित और फोटोकॉपी थीं, इस प्रकार अविश्वसनीय थीं। इसके अलावा, जब नोटिसकर्ताओं ने मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज, हांगकांग से संपर्क किया, तो यह स्वीकार किया गया कि कर्मचारियों की ओर से त्रुटि के कारण, निर्यात

घोषणाओं में माल का मूल्य गलत तरीके से दिखाया गया था। गलती को बाद में सुधार दिया गया जिसके बाद मेसर्स एराइज एंटरप्राइजेज ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष घोषणाओं का दूसरा सेट दर्ज किया और जुर्माने का भुगतान किया जो लगाया गया था।

5.4. यह कहा गया था कि नोटिस पाने वालों को हांगकांग के आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किया गया था कि ट्यूनर, सॉ फिटर आदि को कम कीमतों पर स्टॉक क्लियरेंस के आधार पर उन्हें दिया जा रहा था। यही कारण था कि नोटिसकर्ताओं को कम कीमतों पर माल बेचा गया था, जिसका विवरण जवाब के पैराग्राफ 11 में उल्लेख किया गया था।

5.5. ऐसा कहने के बाद, यह बताया गया कि निर्यात घोषणाओं और आयात चालानों में अलग-अलग कीमतों का मतलब यह नहीं था कि निर्यात घोषणाओं में दिखाई गई कीमत सही थी और आयात चालानों में घोषित कीमत गलत थी।

5.6. जवाब में मूल्यांकन के तरीके के साथ-साथ भारत में सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा माल के मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के विभिन्न प्रावधानों को स्वीकार करने के बाद, यह दावा किया गया कि जिस कीमत पर उत्तरदाताओं के माल का मूल्यांकन किया गया और उसे मंजूरी दी गई, वह कमोबेश सही थी। यह बताया गया कि विभाग माल के तथाकथित सही मूल्य पर पहुंचने के लिए कोई एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। समान या समान वस्तुओं का कोई मूल्य उत्पादन नहीं किया जा सकता था। बाजार मूल्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। तुलना के लिए प्रति इकाई कीमत निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, मूल्यांकन के तहत स्थापित करने के लिए कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि चालान मूल्य से अधिक धन कैसे भेजा गया था। विभाग द्वारा भरोसा किया गया एक और एकमात्र 'साक्ष्य' निर्यात घोषणाओं में दिखाया गया प्रारंभिक मूल्य था जिसे 181 द्वारा गलत घोषित किया गया था।

ग्राहक आयोग (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 182

स्वयं आपूर्तिकर्ता और बाद में संशोधित। इस प्रकार, माल के विवरण या माल के मूल्य के संबंध में कोई गलत घोषणा नहीं थी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और 111 (एम) के तहत विश्वासघात का कोई सवाल नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, माल निषिद्ध नहीं थे, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दिए जाने पर माल को कारण बताएँ नोटिस जारी होने से बहुत पहले नोटिसियों द्वारा बेचा गया था। इसलिए, इस तरह के सामानों की कोई सीमा नहीं हो सकती है। अब तक रु. श्री यशपाल शर्मा द्वारा 30 लाख रुपये का संबंध है, वही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को पूरा करने के लिए था। चूंकि सीमा शुल्क का कोई छोटा भुगतान नहीं था, इसलिए उपरोक्त राशि के विनियोग का सवाल ही नहीं उठा; न तो कोई जुर्माना

लगाया जा सकता था और न ही ब्याज लगाया जा सकता था। मैसर्स गणपति ओवरसीज ने इसलिए आयुक्त से कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया।

6. उत्तरदाताओं का जवाब स्वीकार्य नहीं पाया गया। इसलिए, मामले को निर्णय के लिए लिया गया था। तदनुसार, मामले को निर्णय के उद्देश्य से सीमा शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन-1), न्यू कस्टम्स हाउस, मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया था। निर्णय प्रक्रिया के दौरान, उत्तरदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का आदेश दिया गया था।

6.1. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने नोट किया कि सीमा शुल्क विभाग ने माल के कम मूल्यांकन का आरोप लगाया था जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की चोरी हुई थी।

1,16,09,181.00। मूल्यांकन के तहत साबित करने के लिए, विभाग ने उन्नीस खेपों के संबंध में हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित मूल्य पर भरोसा किया था। इस प्रकार घोषित मूल्य को सही लेन-देन मूल्य माना जाता था। एक और खेप के संबंध में जहां निर्यात घोषणा उपलब्ध नहीं थी, विभाग ने अन्य निर्यात घोषणाओं के आधार पर माल की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किए गए दो मामलों के तथ्यों को अलग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह विचार रखा कि भले ही राजस्व खुफिया निदेशालय के पास उपलब्ध निर्यात घोषणाओं की प्रतियां सत्यापित नहीं की गई हों या जेरॉक्स प्रतियां हों, लेकिन यह उन प्रतियों को अविश्वसनीय या अप्रामाणिक नहीं बनाएगा। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपूर्तिकर्ता मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज ने स्वीकार किया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

यह कि वे घोषणाएँ उनके नेतृत्व में की गई थीं, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि निर्यात घोषणाओं की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, भले ही वे अप्रामाणित हों और मुख्य रूप से जेरॉक्स प्रतियाँ हों। तदनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि प्राप्त जानकारी सही और वास्तविक थी।

6.2. इस तर्क पर कि श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयान स्वैच्छिक नहीं थे और इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि दोनों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज अपने बयानों में माल की कीमत को कम-चालान करने की बात स्वीकार की थी और स्वेच्छा से रुपये का भुगतान किया था। जाँच के दौरान सीमा शुल्क की चोरी के भुगतान के लिए 30 लाख। उन्होंने अपने बयानों में उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली और विभिन्न राशि के हस्तांतरण के तरीके को भी समझाया था। इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने राय दी कि उनके पास प्रत्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करने का

कोई कारण नहीं है कि श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयान स्वैच्छिक नहीं थे और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस याचिका को केवल एक विचार के रूप में लिया गया था।

6.3. उत्तरदाताओं का तर्क कि समकालीन आयातों की तुलना में घोषित मूल्य सही था, निर्णय प्राधिकरण द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि समकालीन आयातों के चालान उत्पादों की विशिष्टता, गुणवत्ता आदि को प्रकट नहीं करते थे।

6.4. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आपूर्तिकर्ता मेसर्स एराइज एंटरप्राइजेज ने स्टॉक निकासी के आधार पर कम कीमत पर माल खरीदा था और इस कारण से वह माल को मेसर्स गणपति ओवरसीज को कम कीमत पर बेच सकता था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुसार, यह फिर से एक विचार और एक आविष्कार तर्क था क्योंकि नोटिसकर्ताओं ने यह घोषणा नहीं की थी कि माल स्टॉक लॉट में खरीदा गया था। न तो चालान और न ही निर्यात घोषणाओं के साथ-साथ प्रवेश के बिल या रिकॉर्ड पर किसी अन्य दस्तावेज से पता चलता है कि सामान को सामान्य से कम कीमत पर स्टॉक लॉट में खरीदा गया था। बल्कि, इस तरह की याचिका विभाग के इस आरोप का समर्थन करेगी कि चालान मूल्य एक सामान्य मूल्य नहीं था और इस तथ्य के साथ कि पक्ष रिश्तेदार थे, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 2 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में मूल्यांकन के लिए चालान मूल्य को अस्वीकार्य बना दिया था। चूंकि न तो समान वस्तुओं का लेन-देन मूल्य और न ही 183

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 184

समकालीन मूल्य आदि उपलब्ध थे, माल के आकलन योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियम 5, 6 और 7 का सहारा लेना संभव नहीं था। इसलिए, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 को सही ढंग से लागू किया गया था।

6.5. यह मानते हुए कि निर्यात घोषणाओं ने वास्तविक लेनदेन मूल्य को प्रतिबिंबित किया, जिसे आयातक द्वारा सीमा शुल्क से बचने के लिए गलत घोषित किया गया था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 17.06.2002 के मूल आदेश के माध्यम से माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 (1) का प्रावधान लागू था। नतीजतन, मेसर्स गणपति ओवरसीज को 500 करोड़ रुपये के अलग-अलग सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। ब्याज के साथ तुरंत 1,16,09,181.00। गलत घोषणा और कम मूल्यांकन के लिए, विचाराधीन माल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और 111 (एम) के तहत प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। हालाँकि, चूंकि उक्त सामान उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मंजूरी के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 114 ए के तहत जुर्माने के रूप में मेसर्स गणपति ओवरसीज पर अलग-

अलग सीमा शुल्क की समतुल्य राशि लगाई गई थी और इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (ए) के तहत श्री यशपाल शर्मा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

7. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के उपरोक्त मूल आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी जो 2002 की अपील संख्या सी/1347 और 1374 के रूप में पंजीकृत थीं।

7.1. सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने राय दी कि हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं पर मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह एक से अधिक कारणों से था। सबसे पहले, वे घोषणाएँ अप्रमाणित फोटोकॉपी थीं। दूसरा, आपूर्तिकर्ता ने घोषणाओं के एक अन्य समूह का नेतृत्व किया था जो आयात के चालान में दिखाए गए मूल्य को दर्शाता है। तीसरा, गलत भाषा घोषणाओं के लिए, जिन्हें बाद में घोषणाओं के एक अन्य सेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, विदेशी आपूर्तिकर्ता ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष जुर्माना अदा किया था। चौथा, सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा कोई जांच नहीं की गई और हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण ने इसके विपरीत कुछ भी खुलासा नहीं किया। उस आधार पर, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने माना कि प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं में दिखाई गई कीमत माल के मूल्य को बढ़ाने का आधार नहीं बन सकती है।

7.2. सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने नोट किया कि आयातकों से पाठ संदेश आदि के रूप में कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने यह भी दर्ज किया कि समकालीन आयात का कोई सबूत नहीं था जिसका मूल्य अधिक था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

विदेशी आपूर्तिकर्ता ने निर्यात घोषणाओं में शुरू में घोषित मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण दिया था, जिसे खारिज नहीं किया गया था। 7.3. सी. ई. एस. टी. ए. टी. के अनुसार, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के तहत आकलन योग्य मूल्य का पता लगाने के लिए निर्यात घोषणा में मूल्य पर भरोसा किया जा सकता है, न कि उस मूल्य का निर्धारण करने के लिए जिस पर सामान आम तौर पर आयात के समय और स्थान पर बेचा जाता है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सीमा शुल्क आयुक्त में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया,

कलकत्ता बनाम दक्षिण भारत टेलीविजन (पी) लिमिटेड, (2007) 6 एस. सी. सी. 373 जिसमें यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तुलनीय आयात के बारे में साक्ष्य या जानकारी द्वारा मूल्यांकन के तहत साबित करने का भार विभाग पर है और यदि कम मूल्यांकन का आरोप ऐसे साक्ष्य या जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, तो संदेह का लाभ आयातक को दिया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के आधार पर, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दर्ज किया कि न केवल समकालीन

आयात का कोई विपरीत प्रमाण था, बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने भी संतोषजनक ढंग से समझाया था कि निर्यात घोषणाओं में शुरु में दिखाई गई कीमत गलत थी जिसे बाद में हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा संशोधित और स्वीकार कर लिया गया था।

7.4. श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयानों के संबंध में न्यायाधिकरण ने कहा कि इन बयानों को जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा लिए गए निर्णय, अर्थात्, सुरजित सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ, 1997 (89) ई. एल. टी.-646 और के. आई. पावन्नी बनाम सहायक कलेक्टर, (1997) 3 एस. सी. सी. 721 ने विभाग के मामले को आगे नहीं बढ़ाया। न्यायाधिकरण ने कहा कि उक्त निर्णयों में, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के इकबालिया बयान के दोषारोपण वाले हिस्से को, भले ही वापस लिया गया हो, आधार दोषसिद्धि पर भरोसा किया जा सकता है यदि यह स्वैच्छिक और सच्चा पाया जाता है; हालाँकि, इस अदालत ने सावधानी बरतते हुए कहा कि विवेक और व्यवहार के लिए आवश्यक होगा कि इस तरह के इकबालिया बयान की पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों द्वारा की जानी चाहिए। श्री यशपाल शर्मा का बयान कि ट्यूनों का वास्तविक बाजार मूल्य रु। 200.00 और रु। 325.00 प्रति टुकड़ा जो इसकी बाजार कीमत रुपये से अधिक कर देगा। 700.00 को जोड़ने के बाद सामान्य प्रोफिट को स्वैच्छिक और सही नहीं माना जा सकता था क्योंकि उत्तरदाताओं को चार अलग-अलग दरों यानी HK \$4.00, 4.50, 5.50 और 6.00 की बातचीत की कीमत पर ट्यूनों की आपूर्ति की गई थी। मामले के उस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण का विचार था कि विभाग द्वारा प्रस्तावित भारित मूल्य 185 के बाद से सही नहीं होगा।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 186

प्रस्तावित फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) कीमत लगभग रु। 372.00 प्रति टुकड़ा और CIF (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य रु। 454.00 प्रति टुकड़ा और उतरने की लागत रु। सीमा शुल्क जोड़ने के बाद 660.00 प्रति टुकड़ा। 7.5. सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने यह भी नोट किया कि आयातकों यानी उत्तरदाताओं ने मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मेसर्स के. एस. इंटरनेशनल द्वारा समकालीन आयातों के चालान प्रस्तुत किए थे ताकि उनके द्वारा घोषित मूल्य के साथ तुलनीय मूल्य दिखाया जा सके।

7.6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने 27.06.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से कहा कि आयातित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ लगाए गए दंड को बनाए नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में अपीलों को अनुमति दी गई।

8. यह सी. ई. एस. टी. ए. टी. का आदेश है जो हमारे समक्ष दो अपीलों में विवादित किया गया है।

9. इस अदालत ने 24.07.2009 दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया था। इसके बाद, 10.12.2010 पर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया।

10. उत्तरदाताओं ने श्री यशपाल शर्मा के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की है। तथ्यों का वर्णन करने के बाद, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी द्वारा उठाए गए सभी तर्कों का विरोध करते हुए सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है। इसलिए, प्रत्यर्थियों ने अपीलों को खारिज करने की मांग की है।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रुपेश कुमार ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णय और आदेश की आलोचना की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अपीलकर्ता को हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित वस्तुओं के घोषित मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 के तहत आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत चालान वास्तविक और वास्तविक लेनदेन का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

11.1. चालान में घोषित मूल्य हांगकांग में निर्यात घोषणाओं में घोषित मूल्य से बहुत कम था। चूंकि यह सही लेन-देन मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता था, इसलिए आयात चालान में दिखाई देने वाला मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 4 के मानदंडों को पूरा नहीं करता था, जिसके अनुसार आयातित माल का लेन-देन मूल्य भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर वास्तव में भुगतान या देय मूल्य होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

11.2. वह प्रस्तुत करता है कि हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाएं विषय वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने का एकमात्र आधार नहीं थी। मूल्यांकन के तहत साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी। आपूर्तिकर्ता एफ. आई. आर. एम. के निदेशक श्री सुरेश चंद्र शर्मा और आयातक के मालिक श्री यशपाल शर्मा दोनों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयानों में मूल्यांकन के तहत स्वीकार किया था। श्री यशपाल शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि आपूर्तिकर्ता मेसर्स एरिस एंटरप्राइजेज, हांगकांग उनके सह-भाई श्री सुरेश चंद्र शर्मा का था। श्री सुरेश चंद्र शर्मा अपने दम पर सामान भेजते थे और उन्होंने कभी भी आपूर्ति के लिए कोई लिखित या मौखिक आदेश नहीं भेजा था। मेसर्स एराइज एंटरप्राइजेज जब भी माल भेजेगा, श्री सुरेश चंद्र शर्मा श्री यशपाल शर्मा को टेलीफोन पर सूचित करेंगे कि माल किसे, किस मात्रा में और किस कीमत पर बेचा जाना है। इसके बाद, वह तय मूल्य पर सामान बेचता था और भुगतान प्राप्त करता था। उन्होंने कहा था कि उन्हें हांगकांग से आयातित वस्तुओं की वास्तविक कीमत के बारे में पता नहीं है। आयात दस्तावेजों के अनुसार भुगतान की राशि उनके द्वारा श्री सुरेश चंद्र शर्मा को बैंकिंग चैनल के

माध्यम से भेजी गई थी और शेष राशि जो वे जब भी भारत आते थे, श्री सुरेश चंद्र शर्मा को सौंपते थे।

11.3. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि हांगकांग में आपूर्तिकर्ता और भारत में आयातक संबंधित पक्ष थे। इसलिए, यह तर्क कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने निर्यात घोषणाओं के एक अन्य समूह का नेतृत्व किया था, जिसमें चालान में दिखाई गई कीमत भारत में आयात दस्तावेजों में दिखाई गई कीमत से मेल खाती थी, सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को विफल करने के लिए एक विचार था।

11.4. वह आगे प्रस्तुत करता है कि जहां उत्तरदाताओं जैसे आयातक ने चालान मूल्य को लेनदेन मूल्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई आधार नहीं रखा था, तो अधिकारियों को सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के तहत नियम 5 के तहत मूल्य निर्धारण शुरू करने के लिए कानूनी रूप से उचित ठहराया जाएगा। उनके अनुसार, विभाग को नियम 5, 6 और 7 के माध्यम से आगे बढ़ने के बजाय उपरोक्त नियमों के नियम 8 का तुरंत सहारा लेना पड़ा क्योंकि न तो समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य और न ही समकालीन कीमतें उपलब्ध थीं। इसलिए, निर्णय देने वाले प्राधिकरण ने सीमा शुल्क के छोटे शुल्क को निर्धारित करने और जुर्माना लगाने के लिए लेनदेन मूल्य का आकलन करते समय नियम 8 को सही तरीके से लागू किया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. को 187 में हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया गया था।

ग्राहक आयोग (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 188

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का ऐसा तर्कपूर्ण आदेश। इन परिस्थितियों में, वह सी. ई. एस. टी. ए. टी. दिनांकित 27.06.2008 के आदेश को दरकिनार करना चाहता है। **12.** इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री वी. लक्ष्मीकुमारन ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि विभाग की अपीलों में पूरी तरह से योग्यता का अभाव है और इसलिए उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। **12.1.** वह प्रस्तुत करता है कि

न्यायाधिकरण ने यह ठहराते हुए पूरी तरह से न्यायसंगत ठहराया कि आयात चालान में घोषित मूल्य सही था। विदेशी आपूर्तिकर्ता ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष पहले प्रस्तुत मूल निर्यात घोषणाओं को वापस ले लिया था और उसके बाद घोषणाओं का एक और सेट शुरू किया था जिसमें घोषित मूल्य आयात चालान में उत्तरदाताओं द्वारा दिखाई गई कीमत से मेल खाता था। बाद की घोषणाओं को हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसके बाद जुर्माना लगाया गया जो आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था।

12.2. विद्वान वकील श्री लक्ष्मीकुमारन प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा जिन निर्यात घोषणाओं पर भरोसा किया गया था, वे केवल फोटोकॉपी थीं जिन पर न तो हस्ताक्षर किए गए थे और न ही सत्यापित किए गए थे। इस प्रकार, उन निर्यात घोषणाओं का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आयात चालान में निकाला गया मूल्य ही बिक्री के लिए

एकमात्र विचार था जो सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 4 के अनुसार लेनदेन मूल्य की अवज्ञा को संतुष्ट करता है।

12.3. श्री वी. लक्ष्मीकुमारन के अनुसार, सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष कम मूल्यांकन साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। श्री सुरेश चंद्र शर्मा और श्री यशपाल शर्मा के बयानों पर एक से अधिक कारणों से कम मूल्यांकन साबित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सका। सबसे पहले, जब दोनों बयान दर्ज किए गए तो सीमा शुल्क विभाग के पास कम मूल्यांकन साबित करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं था। दूसरा, दोनों कथन लगभग समान थे और एक-दूसरे से मेल खाते थे जो इंगित करते हैं कि वे निर्देशित थे। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वे जबरदस्ती और अनुचित दबाव में प्राप्त किए गए थे। तीसरा, दोनों कथनों को पहले उपलब्ध अवसर पर वापस ले लिया गया। चौथा, नई दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने श्री यशपाल शर्मा को जमानत देते हुए अपने दिनांक 1 के आदेश में दर्ज किया था कि दिया गया बयान जबरदस्ती और दबाव में था और इसलिए, इसे स्वैच्छिक बयान नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण को उपरोक्त दो बयानों को कोई विश्वसनीयता नहीं देने में पूरी तरह से न्यायोचित ठहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

12.4. वह आगे प्रस्तुत करता है कि हालाँकि अपीलार्थी ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया था कि पक्ष संबंधित हैं और निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट की भाषा एक विचार के बाद की बात थी, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसके विपरीत, यह रिकॉर्ड में है कि निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट को हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाकर स्वीकार किया गया था जो हांगकांग आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था।

12.5. यह कहते हुए कि आयातित वस्तुओं का कोई कम मूल्यांकन नहीं था, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों द्वारा नियंत्रित होता है न कि किसी अन्य देश में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई मूल्य घोषणा द्वारा। अपीलार्थी को लेन-देन मूल्य का निर्धारण करते समय और सीधे नियम 8 का आह्वान करते हुए सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 5, 6 और 7 को पारित करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था। सीमा शुल्क विभाग ने समकालीन रूप से आयातित समान या समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य को निर्धारित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए कोई प्रभाव नहीं डाला था। इस संबंध में, विद्वान वकील ने रवींद्र चंद्र पॉल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, (2007) 3 एस. सी. सी. 93 और साउथ इंडिया टेलीविजन (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या अनिश्चितता नहीं थी। नतीजतन, अपील खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

13. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा देल गेल निवेदन सभ पर न्यायालय द्वारा उचित विचार कयल गेल अछि।

14. प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, तथ्यात्मक कथा का एक संक्षिप्त पुनर्कथन करना प्रासंगिक होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा प्राप्त एक खुफिया सूचना के आधार पर कि मैसर्स गणपति ओवरसीज ने चालान की कीमतों से काफी कम कीमत पर हांगकांग से ट्यूनर आदि का आयात किया था, जिससे भारी सीमा शुल्क से बचा जा सके, उत्तरदाताओं को दिनांक 17.12.1999 का एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस के अनुसार, मैसर्स गणपति ओवरसीज ने 1997-1998 और 1998-1999 वर्षों के दौरान मैसर्स एरीज एंटरप्राइजेज, हांगकांग से ट्यूनर की बीस खेपों का आयात किया था। श्री सुरेश चंद्र शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम शर्मा मैसर्स एराइज एंटरप्राइजेज के निदेशक थे, जबकि श्री यशपाल शर्मा मैसर्स गणपति ओवरसीज के मालिक थे। श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा सह-भाई थे।

14.1. श्री सुरेश चंद्र शर्मा और श्री यशपाल शर्मा के बयान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए थे। उनके 189 में

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 190

संबंधित बयान जो वस्तुतः एक-दूसरे की प्रशंसा करते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में निर्यात घोषणाओं के अनुसार माल की कीमत वास्तविक कीमत को दर्शाती है। आयात पर, उचित सीमा शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए कीमत को जानबूझकर कम रखा गया था। माल की वास्तविक कीमत काफी अधिक थी। वास्तविक मूल्य और घोषित मूल्य के बीच का अंतर भारत में बरकरार रखा गया था, जिसे श्री सुरेश चंद्र शर्मा जब भी भारत आते थे, श्री यशपाल शर्मा से एकत्र करते थे। हालाँकि, दोनों बयानों को बाद में इस आधार पर वापस ले लिया गया कि वे जबरदस्ती और दबाव में प्राप्त किए गए थे। 14.2. श्री यशपाल शर्मा को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत 15.03.1999 पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा 30.03.1999 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जो कि Rs.30 लाख जमा करने पर सशर्त था, जिसे उन्होंने जमा किया था। अपने जमानत आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दर्ज किया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत श्री यशपाल शर्मा द्वारा दिया गया बयान जबरन लिया गया था, और इसलिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

14.3. यह रिकॉर्ड में आया है कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया था कि प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं में घोषित माल की कीमत कर्मचारियों द्वारा की गई गलती के कारण सही नहीं थी। इसके बाद इसने निर्यात घोषणाओं का दूसरा सेट प्रस्तुत किया जिसमें घोषित माल की कीमत भारत में आयात के समय माल की कीमत से मेल

खाती थी। यह हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन जुर्माना के भुगतान पर जो आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था।

14.4. चाहे जो भी हो, कारण दर्शाओ नोटिस में ब्याज के साथ उच्च सीमा शुल्क लगाने, आयातित वस्तुओं को अलग-अलग रखने और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

14.5. उत्तरदाताओं ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया। सीमा शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन-1), मुंबई द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस पर निर्णय लिया गया था। अपने ऑर्डर-इन-ओरिजिनल दिनांक **17.06.2002** में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उन्नीस खेपों के संबंध में हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित मूल्य को स्वीकार कर लिया। एक खेप के संबंध में जहां निर्यात घोषणा उपलब्ध नहीं थी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उन्नीस खेपों के संबंध में उल्लिखित मूल्य को स्वीकार कर लिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार कर दिया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

राजस्व खुफिया निदेशालय के पास उपलब्ध निर्यात घोषणाओं को सत्यापित नहीं किया गया था और वे केवल जेरॉक्स प्रतियां थीं। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का विचार था कि केवल इसलिए कि निर्यात घोषणाओं की प्रतियां सत्यापित नहीं की गई थीं या जेरॉक्स प्रतियां थीं, वे अविश्वसनीय या अप्रमाणिक नहीं होंगी। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ता ने उन निर्यात घोषणाओं को स्वीकार किया था। इसलिए, उन्होंने माना कि निर्यात घोषणाओं के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा प्राप्त जानकारी सही और वास्तविक थी।

14.6. उन्होंने उत्तरदाताओं की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयान स्वैच्छिक नहीं थे और इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने कीमत के चालान के तहत स्वीकार किया था और यह इस तथ्य से पुष्ट था कि श्री यशपाल शर्मा ने जांच चरण के दौरान स्वेच्छा से सीमा शुल्क से बचने के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसलिए इस तरह की आपत्ति को केवल एक विचार के बाद माना गया था। **14.7.** उत्तरदाताओं का यह तर्क कि समकालीन आयातों की तुलना में घोषित मूल्य सही है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि समकालीन आयातों के चालान उत्पादों की विशिष्टता, गुणवत्ता आदि को प्रकट नहीं करते हैं। **14.8.** न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आपूर्तिकर्ता ने कम कीमत पर स्टॉक निकासी के आधार पर माल खरीदा था, जिसके कारण वह माल को मेसर्स गणपति को कम कीमत पर बेच सकता था। इस तरह के विवाद को एक विचार के बाद माना गया क्योंकि मेसर्स गणपति ओवरसीज ने स्टॉक क्लीयरेंस के आधार पर माल की खरीद का कोई चालान आदि प्रस्तुत नहीं किया था। चूंकि समान

वस्तुओं का न तो लेन-देन मूल्य और न ही समकालीन आयातों आदि का मूल्य उपलब्ध था, इसलिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि विभाग ने नियम 5,6 और 7 को क्रमिक रूप से देखने के बजाय सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 को उचित रूप से लागू किया था।

14.9. सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में उत्तरदाताओं द्वारा मूल आदेश पर हमला किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने 27.06.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश को दरकिनार कर दिया। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दर्ज किया कि हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं पर आयातित वस्तुओं के घोषित मूल्य को बढ़ाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। विभाग के पास उपलब्ध उन निर्यात घोषणाओं की प्रतियां अप्रमाणित फोटोकॉपी थीं।

191

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 192

इसके अलावा, विदेशी आपूर्तिकर्ता ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट का नेतृत्व किया था, जिसमें आयात के चालान में दिखाए गए मूल्य की घोषणा की गई थी। यह हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन आपूर्तिकर्ता पर जुर्माना लगाने पर जो आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने कहा कि उनके आरोप का समर्थन करने के लिए हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने माना कि प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं में दिखाए गए माल का मूल्य मूल्य बढ़ाने का आधार नहीं बन सकता है। आयातकों से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। सीमा शुल्क विभाग के समक्ष इस बात का कोई सबूत नहीं था कि किसी भी समकालीन आयात का मूल्य अधिक था। इस प्रकार, विभाग साक्ष्य प्रस्तुत करके कम मूल्यांकन साबित नहीं कर सका।

14.10. श्री यशपाल शर्मा और श्री सुरेश चंद्र शर्मा के बयानों के संबंध में सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने कहा कि उन बयानों को जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर वापस ले लिया गया था। किसी भी पुष्टिकारक सामग्री या साक्ष्य के अभाव में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दोनों बयानों को अधिक विश्वसनीयता देने से इनकार कर दिया।

14.11. इसके अलावा, यह देखा गया कि जबकि उत्तरदाताओं ने मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसर्स के. एस. इंटरनेशनल द्वारा समकालीन आयातों के चालान प्रस्तुत किए थे, जो उत्तरदाताओं द्वारा घोषित मूल्य के साथ तुलनीय मूल्य पर थे, उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा संक्षेप में अस्वीकार कर दिया गया था, इसके विपरीत साबित करने के लिए विभाग द्वारा बोझ का निर्वहन किए बिना। **14.12.** ऐसी परिस्थितियों में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने 27.06.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से मूल आदेश को दरकिनार कर दिया और उत्तरदाताओं की अपील की अनुमति दी।

15. जैसा कि हमने देखा है, विभाग और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दोनों ने माल के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष विदेशी आपूर्तिकर्ता के नेतृत्व में प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं पर भरोसा किया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने इसमें हस्तक्षेप किया था। हमारा मानना है कि ऐसा करने में सी. ई. एस. टी. ए. टी. को उचित ठहराया गया था।

16. मूल्य के कम चालान का आरोप लगाते हुए और इस तरह उत्तरदाताओं द्वारा सीमा शुल्क से बचने की कार्यवाही राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी और सीमा शुल्क विभाग द्वारा मुख्य रूप से विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर आगे बढ़ाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं का नेतृत्व किया। यह देखा गया कि निर्यात घोषणाओं में उल्लिखित मूल्य और आयात चालान के अनुसार माल की कीमत में बहुत विसंगति थी। उपरोक्त आरोपों का समर्थन करने के लिए, विभाग ने उन निर्यात घोषणाओं की प्रतियों पर भरोसा किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दरकिनारा कर दिया कि राजस्व खुफिया निदेशालय और विभाग द्वारा भरोसा की गई निर्यात घोषणाओं की प्रतियां सत्यापित नहीं थीं और केवल जेरॉक्स प्रतियां थीं। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का विचार था कि केवल इसलिए कि निर्यात घोषणाओं की प्रतियां केवल जेरॉक्स प्रतियां थीं और सत्यापित नहीं की गई थीं, उक्त तथ्य उन दस्तावेजों को अविश्वसनीय या अप्रमाणिक नहीं बनाता था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने उन घोषणाओं के तथ्य को स्वीकार कर लिया था जिनसे नोटिसकर्ता इनकार नहीं करते थे। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के इस निर्णय को सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा नकार दिया गया था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन घोषणाओं पर मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया जा सकता है, न केवल इसलिए कि वे अप्रमाणित फोटोकॉपी थीं, बल्कि इस कारण से भी कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने समझाया था कि निर्यात घोषणाओं के पहले सेट में गलत कीमत का उल्लेख किया गया था, जिसके लिए उसने निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट का नेतृत्व किया, जिसमें आयात चालान में घोषित मूल्य के साथ संबंधित माल की कीमत का मिलान किया गया था। निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट को हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन शुरू में गलत कीमत दिखाने के लिए, जुर्माना लगाया गया था जो विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने यह भी नोट किया कि सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ कोई जांच नहीं की गई थी जो उत्तरदाताओं के खिलाफ कुछ भी अपराध का संकेत देती है। इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने माना कि निर्यात घोषणाओं के पहले सेट में दिखाया गया मूल्य मूल्य में वृद्धि के लिए कोई विश्वसनीय आधार नहीं बन सकता है।

17. हम सी. ई. एस. टी. ए. टी. के दृष्टिकोण से सहमत हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपीलार्थी द्वारा और इससे पहले राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जिन निर्यात घोषणाओं पर भरोसा किया गया था, वे अप्रमाणित फोटोकॉपी थीं। चूंकि उन दस्तावेजों का उपयोग उत्तरदाताओं के खिलाफ साक्ष्य के रूप में किया गया था, इसलिए यह आवश्यक था कि उन दस्तावेजों को साबित किया गया हो जैसा कि कानून में समझा जाता है। निर्भर दस्तावेजों की बिना सत्यापित फोटोकॉपी का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा, बिना किसी की सच्चाई को साबित किए या अपने पास रखे। यह एक और बात है कि इन दस्तावेजों के आधार को बाद में हटा दिया गया था जब विदेशी आपूर्तिकर्ता 193

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 194

एफ. आई. ने हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट का नेतृत्व किया, जिसमें आयात चालान में घोषित माल की कीमत के बराबर कम कीमत दिखाई गई। हमें निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट के लिए आवश्यक कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, हांगकांग सीमा शुल्क प्राधिकरण ने निर्यात घोषणाओं के दूसरे सेट को स्वीकार कर लिया था, हालांकि प्रारंभिक चरण में कीमत की गलत घोषणा के लिए जुर्माना लगाया गया था। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि विदेशी आपूर्तिकर्ता ने जुर्माना अदा किया था। यदि यह स्थिति है, तो अपीलार्थी के लिए सीमा शुल्क से बचने के उद्देश्य से कम चालान साबित करने के लिए निर्यात घोषणाओं के पहले सेट की अप्रमाणित फोटोकॉपी पर भरोसा करके प्रारंभिक निर्यात घोषणाओं के अनुसार माल की कीमत पर राग अलापने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है।

18. यह हमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज श्री सुरेश चंद्र शर्मा और श्री यशपाल शर्मा के बयानों की ओर लाता है। श्री सुरेश चंद्र शर्मा का बयान 08.03.1999 पर दर्ज किया गया था जबकि श्री यशपाल शर्मा का बयान 15.03.1999 पर दर्ज किया गया था। इस प्रकार दिए गए दो बयानों के पूर्ण विवरण का संदर्भ प्रासंगिक नहीं हो सकता है। श्री सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार, श्री यशपाल शर्मा, जो उनके सह-भाई थे, आयातक मेसर्स गणपति ओवरसीज के मालिक थे। उन्होंने अपने एफ. आई. आर. एम. मेसर्स एरीज एंटरप्राइजेज, हांगकांग के माध्यम से मेसर्स गणपति ओवरसीज को ट्यूनर और सॉ फाइटर की आपूर्ति की थी। उन्होंने कहा कि आयात चालान में दिखाई गई वस्तुओं की कीमत वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाती है। आयात चालान में माल की कीमत को सीमा शुल्क बचाने के इरादे से जानबूझकर कम घोषित किया गया था। माल की वास्तविक कीमत काफी अधिक थी। जहां आयात पर बिक्री के बाद चालान की राशि श्री यशपाल शर्मा उन्हें बैंकिंग माध्यम से भेजते थे, वहीं भारत में अलग-अलग राशि श्री यशपाल शर्मा के पास रहती थी, जो श्री सुरेश चंद्र शर्मा को जब भी भारत आते थे, उसी राशि का भुगतान करते थे।

18.1. श्री यशपाल शर्मा ने भी अपने बयान में कमोबेश वही बात कही है जो श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने कही थी। उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत 15.03.1999 पर ही

गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 30.03.1999 पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था, बशर्ते कि उनके पास रु। एक निश्चित अवधि के भीतर 30 लाख, जिसका उन्होंने भुगतान किया। यह रिकॉर्ड में आया है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांकित जमानत आदेश 26.05.1999 में उल्लेख किया था कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज श्री यशपाल शर्मा का बयान हो सकता है सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

स्वैच्छिक। यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्री यशपाल शर्मा ने अपने दिनांकित पत्र 25.08.1999 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत उनके द्वारा दिए गए बयान को वापस ले लिया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने बयान को वापस लेने के तथ्य को नोट किया और इसलिए, इस तरह के इकबालिया बयान को विश्वास देने से इनकार कर दिया। हमारे विचार में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

19. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति से संबंधित है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर थी, निम्नानुसार निकाली गई है:-

108. साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति।-

(1) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विधिवत सशक्त सीमा शुल्क के किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति वह या तो साक्ष्य देने के लिए या किसी भी जांच में कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए आवश्यक समझता है, जो ऐसा अधिकारी किसी भी माल की तस्करी के संबंध में कर रहा है।

(2) दस्तावेजों या अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कुछ विशिष्ट संपादित दस्तावेजों या चीजों को प्रस्तुत करने के लिए या बुलाए गए व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में एक निश्चित विवरण के सभी दस्तावेजों या चीजों को प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है।

(3) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे सकते हैं; और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या बयान देते हैं और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें पेश करते हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है:

बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 के तहत छूट इस धारा के तहत उपस्थिति के लिए किसी भी मांग पर लागू होगी।

(4) उपरोक्त प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

20. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों को पढ़ने से, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा विधिवत सशक्त सीमा शुल्क के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास अधिकार था

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 196

किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना जिसकी उपस्थिति या तो साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी अन्य चीज को किसी भी जांच में पेश करने के लिए आवश्यक मानी जाए जो ऐसा अधिकारी किसी भी माल की तस्करी के संबंध में कर रहा था। इस प्रकार तलब किया गया व्यक्ति उस विषय के संबंध में बयान देने के लिए बाध्य था जिसकी जांच की जा रही थी। सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इस तरह की जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

21. जबकि हम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 पर हैं, हम साक्ष्य अधिनियम, 1882 की धारा 24 का भी विज्ञापन कर सकते हैं जो एक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है:

24. प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण होने वाला इकबालिया बयान, जब आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक हो।-- एक द्वारा किया गया इकबालिया बयान

अभियुक्त व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति करना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण हुआ प्रतीत होता है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप का संदर्भ होता है, न्यायालय की राय में किसी अधिकारी और पर्याप्त व्यक्ति से कार्यवाही की जाती है, ताकि अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे आधार दिए जा सकें जो उसे उचित लगें, यह मानते हुए कि इसे बनाने से वह कोई लाभ प्राप्त करेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में अस्थायी प्रकृति की किसी बुराई से बच जाएगा।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 को पढ़ने से जो स्पष्ट है वह यह है कि किसी अभियुक्त द्वारा किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण किया गया इकबालिया बयान, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप का संदर्भ है, आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक होगा। इस अदालत ने पंजाब राज्य बनाम बरकत राम 1962 (3) एस. सी. आर. 338 में निर्णय दिया कि सीमा शुल्क अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी नहीं हैं, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इसकी एक संविधान पीठ

रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी.

940 यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क के संग्रह और तस्करी की रोकथाम से संबंधित विशेष शक्तियां सौंपी गई हैं। उस उद्देश्य के लिए, उन्हें उचित संदेह पर किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने, साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी जाती है यदि कोई उचित संदेह है कि ऐसा व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम आदि के तहत अपराध का दोषी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

23. साक्ष्य एकत्र करने के लिए, सीमा शुल्क अधिकारी को किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने या साक्ष्य आदि देने के लिए समन भेजने का अधिकार है। हालाँकि, उसके पास सीमा शुल्क उल्लंघन की जाँच करने की कोई शक्ति नहीं है और न ही उसके पास दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति है। सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होता है। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 167 (8) और 178 (ए) से निपटने के लिए, यह न्यायालय

सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम डी. भूमल, (1974) 2 एस. सी. सी. 544

कि साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत सबूत के दायित्व को नियंत्रित नहीं करते हैं। ऐसी कार्यवाहियों में सीमा शुल्क अधिकारी आपराधिक न्यायशास्त्र और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते थे। यह साबित करने का भार विभाग पर था कि माल तस्करी का था। सबूत के बोझ की घटना पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला मुख्य सिद्धांत यह था कि सबूत की पर्याप्तता और वजन पर उस सबूत के अनुसार विचार किया जाना था जिसे साबित करना एक पक्ष की शक्ति में था और दूसरे पक्ष की शक्ति में था।

24. रमेश चंद्र मेहता (ऊपर) में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत एक इकबालिया बयान की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था, यह मानते हुए कि ऐसा बयान सीमा शुल्क की कार्यवाही में साक्ष्य में स्वीकार्य था क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं।

25. नरेश जे. सुखवानी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1996 में यह अदालत

एस. सी. 522 ने स्पष्ट किया कि सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज बयान नहीं है। यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य है।

26. के. आई. पावन्नी बनाम में इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ। सहायक कलेक्टर, (1997) 3 एस. सी. सी. 721 ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम

के संदर्भ में वापस लिया गया इकबालिया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य होगा। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज एक बयान साक्ष्य में स्वीकार्य है, इस अदालत ने अगले प्रश्न पर विचार किया कि क्या ऐसा बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। आगे सवाल यह था कि क्या एक वापस लिए गए इकबालिया बयान को किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि की आवश्यकता होती है। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करने के बाद इस अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत 197 तक वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने की कोई मनाही नहीं है

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 198

अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करना या उसे अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाना। लेकिन अभ्यास और विवेक के लिए आवश्यक होगा कि अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से पुष्टि प्राप्त करके आश्वासन मांगे।

27. एक बार फिर, भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, आकाशवाणी 2009 में

एस. सी. 254, इस न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के प्रावधान पर बहुत विस्तार से विचार किया और उसके बाद कहा कि उक्त धारा समन किए गए व्यक्ति को किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य करती है जिसके संबंध में उसकी जांच की जा रही है। वह इस आधार पर सच बोलने से मुक्त नहीं है कि इस तरह का बयान सबूत में स्वीकार्य है और उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रावधान कस्टम अधिकारी को जांच किए गए व्यक्ति से सच्चाई को उजागर करने में सक्षम बनाता है। धारा 108 का अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति से पूछताछ करने वाले अधिकारी को घटना से संबंधित सभी सच्चाई मिल जाए। हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष बयान देने के लिए बुलाया गया व्यक्ति आरोपी नहीं है। धारा 108 के पीछे का पूरा विचार यह है कि उस व्यक्ति से पूछताछ करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को घटना से संबंधित सभी सच्चाई को इकट्ठा करना चाहिए। यदि इस प्रकार निकाला गया कथन असत्य है, तो ऑफिसर के लिए इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों से अलग और अलग हैं। 28. इस प्रकार, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और संबंधित न्यायिक घोषणाओं के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति को तलब किया जाता है और जो धारा 108 के तहत बयान देता है, वह आरोपी नहीं है। हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। धारा 108 का अंतर्निहित उद्देश्य उस व्यक्ति से सच्चाई का पता लगाना है जिसकी सीमा शुल्क उल्लंघन की घटना के संबंध में जांच की जा रही है। चूंकि इसका उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए

सीमा शुल्क अधिकारियों को इस प्रकार दर्ज किए गए बयान की सच्चाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि अभिलिखित कथन सही नहीं है, तो इस तरह के कथन को अभिलिखित करने की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। यह इस संदर्भ में है कि सीमा शुल्क अधिकारी, जो धारा 108 के तहत बयान दर्ज करने आदि के लिए सशक्त है, की यह सुनिश्चित करने की भारी जिम्मेदारी है कि बयान को निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज किया जाए ताकि संबंधित व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान की जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बयान

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस प्रकार अभिलिखित, जो साक्ष्य में स्वीकार्य है, बुनियादी न्यायिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के मानकों को पूरा कर सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि जब कोई बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है, तो उसे न्यूनतम न्यायिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निश्चित रूप से दबाव या जबरदस्ती के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह पता लगाना है कि क्या इस तरह के बयान की रिकॉर्डिंग में कोई दबाव या जबरदस्ती थी क्योंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

29. आगे बढ़ते हुए, हमें पता चलता है कि विभाग ने आयात चालान के अनुसार घोषित मूल्य को अस्वीकार करने के बाद, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 5, 6 और 7 को क्रमिक रूप से देखने के बजाय सीधे नियम 8 को लागू किया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाताओं की इस दलील को अस्वीकार करने के बाद इसे मंजूरी दी गई कि मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसर्स के. एस. इंटरनेशनल द्वारा समान वस्तुओं के समकालीन आयात की कीमतें आयात चालान में उत्तरदाताओं द्वारा घोषित कीमतों के साथ तुलनीय थीं।

30. इस पहलू से निपटने से पहले, हम प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विज्ञापन कर सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (41) 'मूल्य' अभिव्यक्ति की अवहेलना करती है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वस्तु के संबंध में 'मूल्य' का अर्थ है धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया उसका मूल्य। 10.10.2007 इस परिभाषा को धारा 14 की उप-धारा (2) को भी शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

31. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 वस्तुओं के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। 2007 में संशोधन से पहले, धारा 14 को निम्नानुसार पढ़ा गया था:

14. निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन-(1)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए जहां सीमा शुल्क का शुल्क किसी भी माल पर उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभावी है, ऐसे माल का मूल्य माना जाएगा -

वह मूल्य जिस पर ऐसी या ऐसी वस्तुओं को आम तौर पर बेचा जाता है, या बिक्री के लिए बेच दिया जाता है, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर वितरण के लिए, पाठ्यक्रम या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जहां -

(a) विक्रेता और खरीदार की एक दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है; या 199

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 200

(ख) उनमें से एक की दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है, और बिक्री या बिक्री के लिए मूल्य एकमात्र विचार है: बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया जाता है, या धारा 50 के तहत शिपिंग बिल या निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाता है।

(1 क) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयातित वस्तुओं के संबंध में उस उप-धारा में निर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं के किसी भी वर्ग के लिए ऐसे या समान माल के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शुल्क मूल्य निर्धारित कर सकता है और जहां ऐसे कोई शुल्क मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, वहां शुल्क ऐसे शुल्क मूल्य के संदर्भ में प्रभावी होगा। (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "विनिमय की दर" से विनिमय की दर अभिप्रेत है-(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित, या

((ख) बोर्ड द्वारा निर्देशित तरीके से अभिनिर्धारित,

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए;

(ख) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एम) और खंड (क्यू) में क्रमशः दिया गया है।" 32. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 156 केंद्र सरकार को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने की सामान्य शक्ति प्रदान करती है।

33. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 22 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1963 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 (पहले से ही 'सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम' के रूप में संदर्भित) बनाए गए। 33.1.नियम 2 (1) (सी) "समान वस्तुओं" को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है आयातित वस्तुएँ -

((i) जो भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता और मूल्य की जा रही वस्तुओं के रूप में प्रतिष्ठा सहित सभी मामलों में समान हैं, सिवाय रूप में मामूली अंतर के जो माल के मूल्य को प्रभावित नहीं करते हैं; (ii) उस देश में उत्पादित किया गया जिसमें मूल्यवान माल का उत्पादन किया गया था; और

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया जिसने माल का उत्पादन किया था या जहां ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, एक अलग व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल। हालांकि, ऐसी वस्तुओं में आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होंगी जहां भारत में किए गए इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या रेखाचित्र खरीदार द्वारा इन आयातित वस्तुओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त में या इन आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए कम लागत पर पूरे किए गए थे।

33.2. इसी तरह, धारा 2 (1) (ई) "समान वस्तुओं" का अर्थ आयातित वस्तुओं से है -

(i) हालांकि सभी पहलुओं में समान नहीं हैं, लेकिन समान विशेषताएँ और समान घटक सामग्री हैं जो उन्हें समान कार्य करने में सक्षम बनाती हैं और गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और ट्रेडमार्क के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मूल्यवान वस्तुओं के साथ व्यावसायिक रूप से विनिमेय होने में सक्षम बनाती हैं।

((ख) उस देश में उत्पादित किया गया जिसमें मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया गया था; और

((ग) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जो मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करता है, या जहां ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, वहां एक अलग व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुएं;

लेकिन इसमें आयातित सामान शामिल नहीं होंगे जहां भारत में किए गए इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या रेखाचित्र 201 के खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे किए गए थे।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जवल भुवन, जे.] 202

ये आयातित वस्तुएं इन आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए मुफ्त या कम लागत पर हैं।

33.3.नियम 2 (1) (च) "लेन-देन मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य है। 33.4.नियम 2 (2) में उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जहां व्यक्तियों को "संबंधित" माना जाएगा। वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, जो प्रासंगिक हो सकता है वह नियम 2 (2) (viii) है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को केवल तभी "संबंधित" माना जाएगा जब वे एक ही परिवार के सदस्य हों। इसलिए सवाल यह है कि क्या सह-भाइयों को एक ही परिवार का सदस्य माना जा सकता है? हालाँकि, अन्य मुद्दों के संबंध में हमारी चर्चाओं को देखते हुए इस पहलू पर अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

34. सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का नियम 3 इस प्रकार है:

3. मूल्यांकन की विधि का निर्धारण-के उद्देश्य के लिए

ये नियम, -

((i) आयातित वस्तुओं का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा।

((ii) यदि मूल्य का निर्धारण उपरोक्त खंड (i) के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य का निर्धारण इन नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से किया जाएगा।

34.1. इस प्रकार, नियम 3 के अनुसार, आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन लेन-देन मूल्य होगा। हालाँकि, यदि उस मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य का निर्धारण सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से किया जाएगा।

35. यह हमें नियम 4 में व्यवहार मूल्य पर लाता है जो निम्नानुसार है:

4. लेन-देन मूल्य।— (1) आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य होगा, जिसे इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत आयातित वस्तुओं का लेनदेन मूल्य स्वीकार किया जाएगा:

बशर्ते कि -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(क) खरीदार द्वारा माल के स्वभाव या उपयोग के बारे में प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं हैं जो -

((i) भारत में कानून द्वारा या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित या अपेक्षित हैं; या

((ii) उस भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें माल को फिर से बेचा जा सकता है; या (iii) माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करता है;

(ख) बिक्री या मूल्य उसी शर्त या विचार के अधीन नहीं है जिसके लिए माल के मूल्य के संबंध में मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है;

(ग) खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता को नहीं मिलेगा, जब तक कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है; और

(घ) खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं, या जहाँ खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, वह लेनदेन मूल्य नीचे दिए गए उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है।

(3)(क) जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि आयातित वस्तुओं की बिक्री की परिस्थितियों की जांच से संकेत मिलता है कि संबंध ने कीमत में वृद्धि नहीं की है।

(ख) संबंधित व्यक्तियों के बीच बिक्री में, लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा, जब भी आयातक यह प्रदर्शित करता है कि माल का घोषित मूल्य उसी समय या उसके आसपास निर्धारित किए गए निम्नलिखित मूल्यों में से किसी एक के करीब होता है -

(i) भारत में असंबंधित खरीदारों को बिक्री में समान वस्तुओं या समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य;

((ii) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए कटौती मूल्य; (iii) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए संगणित मूल्य।

बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यों को लागू करने में, नियम 203 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक स्तरों, मात्रा स्तरों, समायोजन में प्रदर्शित अंतर को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 204

9 इन नियमों और बिक्री में विक्रेता द्वारा की गई लागत जिसमें वह और खरीदार संबंधित नहीं हैं;

(ग) इस उप-नियम के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत प्रतिस्थापन मूल्य स्थापित नहीं किए जाएंगे।

36. विवरण को पूरा करने के लिए, हम उल्लेख कर सकते हैं कि जहां नियम 5 समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य से संबंधित है, वहीं नियम 6 समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य से संबंधित है। दूसरी ओर, नियम 6 ए लेनदेन मूल्य उपलब्ध नहीं होने पर मूल्य के निर्धारण का प्रावधान करता है। नियम 7 जो नियम 6 ए के बाद आता है, कटौती मूल्य के निर्धारण के लिए प्रदान करता है और नियम 7 ए संगणित मूल्य के लिए प्रदान करता है।

37. जहां आयातित वस्तुओं का मूल्य उपरोक्त नियमों में से किसी के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां मूल्य का निर्धारण नियम 8 में दिए गए उचित साधनों का उपयोग करके किया जाएगा, अर्थात् अवशिष्ट विधि। 38. रवीन्द्र चंद्र पॉल (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत ने आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, (2001) 1 एस. सी. सी. 315 में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया -

6. आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड में बनाम कॉम.सीमा शुल्क के संबंध में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन का सिद्धांत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (1) में पाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय बिक्री मूल्य के आधार पर आकलन योग्य मूल्य के निर्धारण का प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम के तहत माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। धारा 14 (1) के अनुसार, माल के मूल्य पर शुल्क का आकलन किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 14 (2) के तहत मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। जहां मूल्य इतना निश्चित नहीं है, वहां इसे धारा 14 (1) के तहत तय किया जाना है। धारा 14 (1) के अनुसार, मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर ऐसी या ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से बेचा जाता है या बिक्री के लिए बेचा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान समय और स्थान पर वितरण और आयात के लिए। "आम तौर पर" शब्द का अर्थ विशेष परिस्थितियों का बहिष्कार है। इस स्थिति को धारा 14 (1) के अंतिम वाक्य द्वारा स्पष्ट किया गया है जो एक "साधारण" बिक्री का वर्णन करता है जिसमें विक्रेता या खरीदार की एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं होती है और कीमत बिक्री या बिक्री के लिए एकमात्र विचार है। इसलिए, जब विशेष परिस्थितियों के समय, स्थान और अनुपस्थिति के संबंध में उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आयातित वस्तुओं का निर्णय उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ धारा 14 (1-ए) के तहत किया जाएगा। उक्त नियम सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 हैं। यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां नियम 4 (2) (सी) से (एच) में उल्लिखित परिस्थितियां लागू नहीं होती हैं, विभाग लेनदेन मूल्य के तहत शुल्क का आकलन करने के लिए बाध्य है। इसलिए, जब तक कि विशेष लेनदेन के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत नियम 4 (2) (सी) से (एच) में उल्लिखित अपवादों के भीतर नहीं आती है, तब तक विभाग लेनदेन मूल्य पर शुल्क का आकलन करने के लिए बाध्य है। यह भी माना गया कि नियम 4 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा

14 (1) से सीधे संबंधित है। नियम 4 के साथ पठित धारा 14 (1) में यह प्रावधान है कि आयातक द्वारा वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में भुगतान की गई कीमत को धारा 14 (1) में इंगित किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में मूल्य के रूप में लिया जाएगा। इसलिए, मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मूल्य के रूप में जो स्वीकार किया जाना चाहिए वह विशेष लेन-देन के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत है, जब तक कि नियम 4 (2) में निर्धारित कारणों के लिए कीमत अस्वीकार्य न हो। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 4 (1) में "देय" शब्द को "विशेष लेन-देन" के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और लेन-देन के संबंध में देयता को ऐसी स्थिति के रूप में माना जाना चाहिए जहां मूल्य का भुगतान स्थगित हो जाता है। इसलिए, नियम 4 विचाराधीन लेन-देन तक ही सीमित है। यह भी माना गया कि नियम 5 लेन-देन मूल्य को लगभग उसी समय भारत में आयातित समान वस्तुओं के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है; नियम 6 लगभग उसी समय भारत में आयातित समान वस्तुओं के मूल्य के आधार पर लेन-देन मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है। जहां भारत में कोई समकालीन आयात नहीं है, वहां मूल्य नियम 7 के तहत उसमें दिए गए तरीके से कटौती की प्रक्रिया द्वारा तय किया जाना है। यदि यह संभव नहीं है, तो मूल्य की गणना नियम 7-ए के तहत की जाएगी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल तभी होगा जब नियम 4 के तहत लेन-देन मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, केवल तभी नियम 3 (ii) के तहत मूल्य का निर्धारण नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि लेन-देन मूल्य नियम 4 (1) के तहत तय किया जा सकता है और नियम 4 (2) में दी गई किसी भी परिस्थिति में नहीं आता है, तो बाद के नियमों के तहत मूल्य निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी माना गया कि छूट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मान्यता प्राप्त विशेषता है और जब तक वे छूट समान रूप से उपलब्ध हैं और जब तक वे वाणिज्यिक विचारों पर आधारित हैं, उन्हें धारा 14 के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

205

ग्राहक आयोग (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 206

7. सीमा शुल्क मूल्यांकन के लिए प्राथमिक आधार लेन-देन मूल्य है अर्थात् समायोजन के अधीन, आयात के देश में निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य। उक्त मूल्य किसी भी शर्त या विचार के अधीन नहीं होना चाहिए जो नियम 4 (1) के तहत मूल्य निर्धारित होने से रोक सकता है। जहां विभाग के पास किसी घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण है, वह आयातक से इस आशय का और स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि घोषित मूल्य आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि घोषित मूल्य अन्य खरीदारों द्वारा उसी समय या उसके आसपास आयातित समान वस्तुओं के घोषित मूल्य से कम है, तो यह वाणिज्यिक चालान में इंगित घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर "संदेह करने का कारण" हो सकता है (नियम 10-ए देखें)। नियम 8 (2) (i) के तहत भारत में उत्पादित वस्तुओं के बिक्री मूल्य के आधार पर कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां विभाग नियम 4 (2) में

उल्लिखित परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहता है, निर्धारिती द्वारा घोषित लेनदेन मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और चालान में उल्लिखित मूल्य को लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा जाना चाहिए।

39. साउथ इंडिया टेलीविजन (पी) लिमिटेड (ऊपर) में शामिल विवाद था

हांगकांग में विदेशी आपूर्तिकर्ता से आयातक द्वारा आयातित चीनी मिट्टी के संधारित्रों और डायोड के आकलन योग्य मूल्य के संबंध में।आयातक द्वारा घोषित मूल्य को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा विदेशी जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके बाद सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 को लागू किया गया था।इस अदालत ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (41) और धारा 14 (1) की निम्नलिखित तरीके से जांच और विश्लेषण किया:

10. हम निम्नलिखित कारणों से इस दीवानी अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं।मूल्य मूल्य से प्राप्त होता है।मूल्य मूल्य का कार्य है।यह मूल्य का वैचारिक अर्थ है।धारा 2 (41) के तहत, "मूल्य" को अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार निर्धारित मूल्य माना जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 वस्तुओं के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कानून का एकमात्र भंडार है।सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 केवल आयातित वस्तुओं के संबंध में बनाए गए हैं।निर्यात वस्तुओं के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं।यह धारा 14 के आधार पर ही किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में विभाग ने प्रत्यर्थी आयातक पर गलत घोषणा का आरोप लगाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कीमत।माल के विवरण के संदर्भ में गलत घोषणा का कोई आरोप नहीं है।वर्तमान मामले में, आरोप चालान के तहत है।कम चालान के शुल्क को समान वस्तुओं के समकालीन आयात की कीमतों के प्रमाण द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।यह साबित करना विभाग का काम है कि जो प्रत्यक्ष है वह वास्तविक नहीं है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (41) के तहत, किसी भी माल के संबंध में "मूल्य" शब्द का अर्थ धारा 14 (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य है।प्रविष्टि बिल में घोषित किया जाने वाला मूल्य ऊपर निर्दिष्ट मूल्य है न कि केवल चालान मूल्य।11. धारा 14 (1) और धारा 14 (1-ए) के एक सादे पठन पर, यह परिकल्पना की गई है कि अधि-मूल्य शुल्क के लिए प्रभार्य किसी भी माल का मूल्य धारा 14 (1) में निर्दिष्ट मानित मूल्य होना चाहिए।इसलिए, इस तरह के मूल्य का निर्धारण प्रासंगिक नियमों के अनुसार और धारा 14 (1) के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए।यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 14 (1) और धारा 14 (1-ए) परस्पर अनन्य नहीं हैं।इसलिए, नियम 4 के तहत लेन-देन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर ऐसी वस्तुओं पर भुगतान या देय मूल्य होना चाहिए।धारा 14 डीमिंग प्रावधान है।यह मानित मूल्य की बात करता है।मूल्य वह मूल्य माना जाता है जिस पर ऐसी वस्तुओं को आम तौर पर बेचा जाता है या बिक्री के लिए

उतार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए जहां विक्रेता और खरीदार की एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है और कीमत बिक्री के लिए या बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है। इसलिए, विभाग को जो देखना है वह आयात के समय आयातित वस्तुओं का मूल्य या लागत है, यानी उस समय जब माल सीमा शुल्क बाधा तक पहुंच जाता है। इसलिए, चालान मूल्य पवित्र नहीं है।

39.1. इस अदालत ने कहा कि चालान मूल्य को अस्वीकार करने से पहले विभाग को इस तरह की अस्वीकृति के लिए ठोस कारण देने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चालान मूल्य लेनदेन मूल्य का आधार बनता है। इस संबंध में, इस अदालत ने कहा कि कम मूल्यांकन को साबित करना होगा। यदि विभाग मूल्यांकन के तहत आरोप लगाना चाहता है, तो उसे विस्तृत पूछताछ करनी चाहिए, सामग्री एकत्र करनी चाहिए और पर्याप्त सबूत भी देने चाहिए। यदि कम मूल्यांकन के शुल्क का समर्थन साक्ष्य या तुलनीय आयात के बारे में जानकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो संदेह का लाभ आयातक को मिलना चाहिए। चालान के तहत शुल्क 207 होना चाहिए।

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्ज्वल भुवन, जे.] 208

समान वस्तुओं के समकालीन आयात की कीमतों के साक्ष्य द्वारा समर्थित। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

12. हालांकि, चालान मूल्य को अस्वीकार करने से पहले विभाग को इस तरह की अस्वीकृति के लिए ठोस कारण देने होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चालान मूल्य लेनदेन मूल्य का आधार बनता है। इसलिए, लेन-देन मूल्य को गलत या अस्वीकार्य के रूप में अस्वीकार करने से पहले, विभाग को यह पता लगाना होगा कि क्या समान वस्तुओं या समान वस्तुओं का लगभग एक ही समय में अधिक कीमत पर कोई आयात होता है। जब तक उस संबंध में साक्ष्य एकत्र नहीं किया जाता है, तब तक धारा 14 (1-ए) को आयात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, चालान मूल्य को लेनदेन मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। चालान मूल्य का प्रमाण है। आयातक द्वारा प्रस्तुत चालान पर संदेह करना इसे आयातित वस्तुओं के मूल्य के प्रमाण के रूप में अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अवमूल्यन को साबित करना होगा। यदि कम मूल्यांकन के आरोप का समर्थन साक्ष्य या तुलनीय आयात के बारे में जानकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो संदेह का लाभ आयातक को मिलना चाहिए। यदि विभाग अवमूल्यन का आरोप लगाना चाहता है, तो उसे विस्तृत पूछताछ करनी चाहिए, सामग्री एकत्र करनी चाहिए और पर्याप्त सबूत भी देने चाहिए। जब अवमूल्यन का आरोप लगाया जाता है, तो विभाग को इसे तुलनीय आयात के बारे में साक्ष्य या जानकारी द्वारा साबित करना होता है। अवमूल्यन साबित करने के लिए, यदि विभाग निर्यातक देश में की गई घोषणा पर निर्भर करता है, तो उसे यह दिखाना होगा कि ऐसी घोषणा कैसे प्राप्त की गई थी। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि साक्ष्य के सख्त नियम न्यायनिर्णयन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। वे अदालतों की कार्यवाही पर सख्ती से लागू होते हैं। हालांकि, न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में भी, ए. ओ. को उन

दस्तावेजों के संभावित मूल्य की जांच करनी होती है जिन पर विभाग द्वारा अवमूल्यन के अपने आरोप के समर्थन में भरोसा किया जाता है। एक बार जब विभाग उच्च मूल्य पर समकालीन आयात के साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त सीमा तक प्रमाण का भार वहन कर देता है, तो यह स्थापित करने की जिम्मेदारी आयातक पर आ जाती है कि उसके द्वारा भरोसा किया गया चालान वैध है। इसलिए, कम चालान के शुल्क को समान वस्तुओं के समकालीन आयात की कीमतों के प्रमाण द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

39.2. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) की ओर लौटते हुए, इस अदालत ने कहा कि यह साबित करना विभाग का काम है कि चालान का मूल्य गलत है। जब उच्च मूल्य पर समकालीन आयात का कोई प्रमाण नहीं होता है, तो चालान मूल्य स्वीकार किए जाने योग्य होता है। इस अदालत ने यही कहा है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

13. धारा 14 (1) "मानित मूल्य" की बात करती है। इसलिए, चालान मूल्य विवादित हो सकता है। हालाँकि, यह साबित करना विभाग का काम है कि चालान का मूल्य गलत है। जब उच्च मूल्य पर समकालीन आयात का कोई प्रमाण नहीं होता है, तो चालान मूल्य स्वीकार किए जाने योग्य होता है। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के तहत आकलन योग्य मूल्य का पता लगाने के लिए निर्यात घोषणा में मूल्य पर भरोसा किया जा सकता है न कि उस मूल्य का निर्धारण करने के लिए जिस पर आम तौर पर आयात के समय और स्थान पर माल बेचा जाता है। यही वह जगह है जहाँ मूल्य और मूल्य के बीच वैचारिक अंतर चर्चा में आता है।

40. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 3 और 4 वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के समक्ष फिर से विचार के लिए सामने आए। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) के संबंध में, इस अदालत ने निम्नलिखित तरीके से उक्त प्रावधान का विश्लेषण किया:

19. अधिनियम की धारा 14 (1) माल के मूल्य के निर्धारण के लिए एक विधि निर्धारित करती है। यह एक माना जाने वाला प्रावधान है। इस धारा में शामिल कानूनी प्रावधान द्वारा, आयातित वस्तुओं का मूल्य वह मानित मूल्य है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए ऐसी या ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से बेचा या बिक्री के लिए रखा जाता है।

20. धारा 14 (1) में "साधारण रूप से" शब्द एक सार्थक शब्द है। धारा 14 (1) में "सामान्य" शब्द का सामान्य अर्थ "गैर-अपवादात्मक" या "सामान्य" है। इसका मतलब "सार्वभौमिक रूप से" नहीं है। धारा 14 (1) के संदर्भ में माल के "मूल्यांकन" के उद्देश्य से, हालाँकि, "सामान्य रूप से" शब्द का उपयोग करके संकेत यह है कि माल का सामान्य मूल्य वही है जो आयात के

समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान होता। इस प्रकार, धारा 14 (1) में यह प्रावधान है कि मूल्य का निर्धारण परिवहन के समय और स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घटनाओं के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए सामान्य रूप से बेचे गए या बेचे गए सामानों से जुड़ी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। 40.1. सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों में प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से नियम 3 और 4 में, इस अदालत ने आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपरोक्त) में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि आयातक द्वारा विक्रेता को वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में भुगतान की गई कीमत को धारा 14 (1) में इंगित किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में और नियम 4 (2) में विशिष्ट मूल्य माना जाएगा।

209

ग्राहक आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम एम/एस गणपति ओवरसीज टीएचआर। यह प्रोप है। श्री यशपाल शर्मा [उज्जल भुवन, जे.]

हालांकि, जब नियम 4 के तहत लेनदेन मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाएगा। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

23. आयशर ट्रैक्टर्स में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 के अनुसार मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए ऐसी या ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से बेचा या बिक्री के लिए रखा जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 4 (1) द्वारा अधिकारियों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे मूल्यांकन के तहत माल के संबंध में माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य को लेनदेन मूल्य के रूप में स्वीकार करें, लेकिन यह अधिदेश नियम 4 (2) में निर्दिष्ट कुछ अपवादों के अधीन है। इस न्यायालय द्वारा आयशर ट्रैक्टर्स [(2001) 1 एस. सी. सी. 315] में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 14 (1) और नियम 4 दोनों में यह प्रावधान है कि आयातक द्वारा सामान्य वाणिज्य प्रक्रिया में विक्रेता को भुगतान की गई कीमत को धारा 14 (1) में इंगित और नियम 4 (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी विशेष परिस्थिति के अभाव में मूल्य माना जाएगा। हालांकि, जब नियम 4 के तहत लेन-देन मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मूल्य नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाएगा।

40.2. इस अदालत ने रवींद्र चंद्र के फैसलों का भी उल्लेख किया

पॉल (ऊपर) और साउथ इंडिया टेलीविजन (पी) लिमिटेड (ऊपर) दोहराने के लिए

मान्यता प्राप्त कानूनी स्थिति कि यदि चालान मूल्य सही नहीं पाया जाता है तो लेनदेन मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह साबित करना विभाग का काम है कि चालान मूल्य गलत है।

41. इस प्रकार, तथ्यों और कानूनी स्थिति के संचयी विश्लेषण पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि विभाग के साथ-साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दोनों को माल के आयात चालान मूल्य को सही नहीं मानते हुए अस्वीकार करने और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 को सीधे लागू करके कीमत बढ़ाने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था, जब उनके सामने ऐसा करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इन परिस्थितियों में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. को मूल में आदेश को दरकिनार करने के लिए उचित ठहराया गया था। 42. इसलिए हम सी. ई. एस. टी. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि या संदेह नहीं करते हैं। विभाग के नेतृत्व में की गई अपीलें योग्यता से रहित हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन